International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.11 No.2 Nov-Dec 2023

कारगिल युद्ध का रणनीतिक विश्लेषण

डॉ. रमेश प्रसाद कोल
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग,
शासकीय रणविजय प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला उमरिया, म.प्र. भारत, 484661
Corresponding Author – डॉ. रमेश प्रसाद कोल
Email: dr.rameshprasadkol@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.10280139

सारांश–

कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय कहते के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लडने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रू मु इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और गरीब 5000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के बब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे–धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध उॅचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनो देशों की सेनाओं को लडने में काफी मुश्किलों का सामना करना पडा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। औरत ने कारगिल युद्ध जीता।

कीवर्डः– कारगिल युद्ध, जम्मू काश्मीर

प्रस्तावनाः–

कारगिल में पाकिस्तान सैन्य सुरूआत की एक राजनीतिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि है, जो दोनो ओर की जनता को ज्ञात नहीं है कारगिल में पाकिस्तानी कार्यवाही वास्तव में जम्मू एवं कश्मीर पर कब्जा करने के बहुत से प्रयासों का एक हिस्सा था, इसकी जडें कारगिल के उसके अन्य प्रयासों की विफलता में भी थी, खासकर 1989 से 1999 की अवधि के दौरान अपने क्षेत्र विस्तार के दावे को सच करने के लिए पाकिस्तान तर्क रखा कि जम्मू एवं कश्मीर का पाकिस्तार का अंग बनना विभाजन का अपूर्ण कार्य था, चूकि विभाजन दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित था, अतः उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, दूसरा तर्क यह था कि जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए उनसे जनमत संग्रह का वादा किया गया था, जिसे भारत हमेंशा से इंकार करता रहा है, इस पर भी बात नहीं बनी तों पाकिस्तान द्वारा यह कहा जाने लगा कि भारत जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकार का उलंघन कर रहा है। इसलिए इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह कर्तव्य होता है कि वे जम्मू एवं कश्मीर को भारत से आजादी दिलाए जब ये सभी तर्क जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को भारत से आजादी दिलाए। जब ये सभी तर्क जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को भारत के विरूद्ध एकजुट करने में विफल रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो उसने आतंकी घुसपैठ का सहारा लेने लगा, जम्मू एवं कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का हठ आज भी बरकरार है।

ऑपरेशन बद्रः–

पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र द्वारा जम्मू एवं कश्मीर पर हमले के लिए 'ऑपरेशन बद्र आरम्भ किया गया, पाकिस्तान सोचता था कि जम्मू एवं कश्मीर में मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की विश्वसनीयता कम थी और भारतीय सेना और सुरक्षा बल विभिन्न गतिविधियों में इतने लिप्त है कि वे एक अप्रत्याशित सैन्य आक्रमण को रोक पाने में सफल नहीं होंगे। मार्च 1999 में वाजपेयी सरकार लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी सत्ता खो बैठी थी। उस समय भारत सरकार एक कामचलाऊ सरकार थी, जो आम चुनाव में व्यस्त थी। पाकिस्तान का पूर्वानुमान था कि वाजपेई सरकार देश में अस्थिर और अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विदेशी आक्रमकता के विरूद्ध दृढ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगी। पाकिस्तान का अनुमान था कि यदि पाकिस्तानी सेना ने एक बार कारगिल क्षेत्र की हिमालय श्रृंखलाओं की ऊॅचाई पर अपनी व्यूह रचना कर ली, तो भारतीय सेना उनका मुकाबला करने में समर्थ नहीं होगी। उसे यह भी विश्वास था कि यदि भारतीय सेना उस पर भारी पडी तो वह परमाणु अस्त्रों का सहारा लेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा और 1965 और 1971 की तरह युद्ध को विस्तार करके और पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा बताकर अपने इरादे में सफल हो जाएगा।

सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई के प्रमुख ले. जनरल ने 1999 की शुरूआत में पूर्वानुमान जाहिर करते हुए लिखा था कि वर्तमान में भारतीय सेना कोई भी सुव्यवस्थित कार्रवाई करने में असमर्थ है। ऐसी

स्थिति में यह कैसे सोचा जा सकता है कि वे एक सुनिश्चित संर्घष को विस्तार देंगे।

कारगिल युद्ध के प्रमुख योजनाकार– भारत–पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के प्रमुख योजनाकार जनरल मुशर्रफ ही थे, वे मानते थे कि कारगिल युद्ध में उनको विजय अवश्य मिलेगी। उनके अनुमान के अनुसार भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के कमजोर नेतृत्व के कारण भारतीय सेना का मनोबल गिरा हुआ था। 'इंडियन ईंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल स्टडीज' के एक अध्ययन के अनुसार कश्मीर मुद्दे पर मुशर्रफ के दृष्टिकोण का सारांश निम्नलिखित है–

- भारतीय जनता पार्टी 'कागज के शेरों की पार्टी है। मैं सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं।
- पाकिस्तान परमाणु सम्पन्न देश है, उसके पास अति आधुनिक मिसाइलें भी हैं इसकी कारगिल के क्षेत्र में उपस्थिति का सामना भारत नही ंकर पाएगा।
- परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल का भय, पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा।

जनरल मुशर्रफ के अक्टूबर 1998 में हुए साक्षात्कार तथा भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं–

- कश्मीर पर कब्जा बाद में भी किया जा सकता है, यहॉ यह बात महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में भारतीय सेना पर हमले कुछ इस प्रकार किए जाऐं जैसे अफगानिस्तान में सोवियत टुकडियों के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन कर रहे हैं।
- यहॉ यदि कश्मीर मुद्दा सुलझ भी जाए तो भी भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि भारत को चीन और जापान की तरह एक बडी एशियाई शक्ति के रूप में उभरते पाकिस्तान नहीं देख सकता।

सन 1998 से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सरकार को 1999 में सत्ता से बेदखल कर खुद को पाकिस्तान का कार्यकारी प्रमुख घोषित कर दिया, पहले हमें उनके नीतियों को समझना होगा, जो पूरे भारत के सन्दर्भ में क्रियान्वित करना चाहते थे जहॉ तक भारत का सम्बन्ध है, वह राजनीतिक और सैन्य संघर्ष की स्थिति कायम रखने के लिए जाने जाते थे, उनका विश्वास था कि अराजक तत्वों और सैन्य घुसपैठ का निरन्तर अभियान पाकिस्तान को कश्मीर हासिल करने में मदद करेगा, जिया कि भॉति जनरल परवेज मुशर्रफ के भी पाकिस्तान के जमान–ए–इस्लामी से नजदीकी सम्बन्ध थे।

सन 1987 जनरल परवेज मुशर्रफ के कॅरियर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सियाचिन क्षेत्र में भारतीय सेना को पिछे धकेलने के लिए बनाए गए स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का ब्रिगेड कमांडर उन्हे बनाया गया था। सितम्बर 1987 में सियाचिन क्षेत्र के बी लार्फोड ना में भारतीय सैनिक चौकी पर हुए एक बडे आक्रमण के पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ का ही विभाग था। उस समय भी उनकी सेना को भारतीय टुकडियों ने पीछे धकेल दिया था। उन्हे सन 1989 में गिलगित क्षेत्र में सुन्नी बहुल स्थानीय प्रशासन के खिलाफ शियाओं के विद्रोह को दबाने का विशेष दायित्व सौंपा गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस कार्यवाही में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और अफगानिस्तान के पठान कबाइलियों का इस्तेमाल किया था। इस कार्यवाई में सैकडों शियाओं को मार डाला गया। इसके बाद गिलगित और बाल्टिस्तान में पंजाबियों और पठानों को बसाकर गिलगित क्षेत्र का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया गया, ताकि उस क्षेत्र के मूल निवासी कश्मीरी शियाओं की बहुलता कम हो सके।

कारगिल का भू–रणनीतिक महत्व

कारगिल निसंदेह कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचित ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारतीय अधिकार क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के सियाचीन और सालटोरों चोटियॉ तक फैला हुआ है। हमें यहां याद रखना चहिए कि कारगिल घाटी का एक हिस्सा था, परन्तु इस क्षेत्र मं शिया मुसलमानों की बहुलता देखते हुए इस एक अलग जिला बना दिया गया यदि पाकिस्तान गारगिल क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो घाटी से लद्दाख तक का हाइवे नष्ट हो जाता और लद्दाख व सियाचिन से भारत का सम्बंन्ध कट जाता। यदि यह सैन्य संघर्ष परमाणु युद्ध की ओर बढता तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करके पाकिस्तान के इच्छित तरीकों से कश्मीर पर समझौता करने के लिए भारत पर दबाव बनाता। पाकिस्तान की सम्पूर्ण योजनाओं और विस्तृत सैन्य तैयारियों तथा भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार विश्लेषित किया गया–

- इस योजना को बहुत गुप्त रखा जाना था, जिसमें बहुत कम लोग शामिल होते और ऐसी किसी भी गतिविधि को नहीं किया जाता, जिससे पाकिस्तानी इरादा का संकेत मिले।
- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बिना निर्देश के सिर्फ सैद्धान्तिक सहमति ली जानी थी।
- यह कार्यवाई कश्मीर मुद्दे, जिससे विश्व का ध्यान कुछ समय के लिए हटा हुआ था, के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद देती।
- आक्रमण को शुरू करने और समय से पहले तीव्र होने पर नियंत्रण के लिए एक कवर प्लान भी थी।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर पाकिस्तानी सेना ने एक योजना बनाई थी, जो पूर्णतया फेल हो गई। इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान के सैन्य लक्ष्य इन बिन्दुओं पर आधारित थे–

- घुसपैठ से नियंत्रण रेखा की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी।

- घुसपैठ से पाकिस्तान को नियंत्रण देखा के पार प्रभावी भूभागों पर नियंत्रण मिल जाएयगा, इससे समझौते में वह एक मजबूत स्थिति में होगा।
- कारगिल घुसपैठ से उन खाली स्थानों पर लाभ उठाया जा सकता है जो क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के भारत और पाकिस्तान दोनो पक्षों की सुरक्षा व्यवस्था में है। यह भूभाग बहुत उॅचा–नीचा है, जहॉ प्रमुख मांगों में नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाले बहुत कम रास्ते हैं। सर्दियों में यहॉ भारी हिमपात होता है, जिससे यहा कोई गतिविधि लगभग असंभव हो जाती है।

भारत में इस हिंसक प्रदेष की योजनाएं सन को 1998 में बनाई गई और जनवरी 1999 में अंतिम रूप दिया गया। कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों का घुसपैठ एक नियमित सामान्य और विशाल पैमाने की सैनिक घटना नहीं थी। यह काम दो माह की अवधि के दौरान धीरे–धीरे किया गया। यह कार्यवाई एक सुनियोजित प्रयास थी। पाकिस्तान इस आक्रमण के लिए मुख्य रू॰ से नादर्न लाईट इन्फैट्री की टुकडियों पर निर्भर था, क्योंकि इस रेजिमेंट के अधिकतर सैनिक स्कर्दू, पाक अधिकृत कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगित और उत्तर–पश्चिमि पहाडी क्षेत्रों के युवा थे ये भी अधिक ऊॅचाई पर सैन्य गतिविधियों के दक्ष थे। उनको अपनी वर्दियां उतारकर सलवार कमीज पहनने, दाढी बढाने और टोपियॉ पहनने के लिए गहा गया था। उन्हे 3 से 4 या 5 समूहों में बॉटकर पूरे कारगिल क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए कहा गया, जो उन्होने अप्रैल के अंत तक किया। सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए अधिकतम संभव उॅचाई तक सडकों से जानवरों को जाने के लिए मार्ग अलग बनाए गए। कारगिल में उस समय भारतीय सेना की अनुपस्थिति में पाकिस्तानी बलों की स्थिति मजबूत करने के लिए हेलीपैड भी बनाए गए थे इन पाकिस्तानी प्रयासों का एक दिलचस्प आयाम यह भी था कि भाडे के विदेशी आतंकवादियों को छोडकर अनियमित सैनिकों को पोर्टरों और लॉजिस्टिकल सहयोग ले जाने वाले लोगों की तरह इस्तेमाल किया गया। पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों के अन्य भागों से संबंधित ये सैनिक जो नियमित पाकिस्तानी सेना में नहीं थे, को लॉजिस्टिकल श्रम बल के रूप में प्रयुक्त किया गया, पाकिस्तानी सेना की इकाइयों को सहयोग देने के लिए अफगानिस्तान से भाडे के आतंकवादियों और तालिबान के सदस्यों को बुलाया गया था। पाकिस्तानी लडाकूओं के पास उपलब्ध हथियारों और सैन्य सामग्री के साथ–साथ तोपखाना व वायु–सहयोग इस झूठ की पोल खोलते हैं कि कारगिल में पाकिस्तान की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी।

सुब्रह्ाण्यम समिति की रिपोर्टः

सरकार और सुब्रह्ाण्यम समिति की रिपोर्ट द्वारा दिए गए सभी तर्कों के बावजूद यह तथ्य अपने स्थान पर आज भी मौजूद है कि भारतीय अधिकारी कारगिल में लगभग 8 माह तक पाकिस्तान द्वारा की जा रही सैन्य तैयारियों की भनक भी नहीं पा सके। विभिन्न टिप्पणियों और सुब्रह्ाण्यम समिति की रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जो इस प्रकार हैं–

- कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास बढी हुई पाकिस्तानी गतिविधियों के बारे में विभिन्न भारतीय इंटेलिजेंस स्रोतों द्वारा सामान्य सूचनाएं थी।
- इस बात के भी स्पष्ट संकेत थे कि हमारी सेना का फील्ड इंटेलिजेंस मूल्यांकन अपर्याप्त और अनिश्चित था।
- जम्मू एवं कश्मीर में सेना कमांड ने उपलब्ध सूचनाओं को मई 1999 तक किसी बडी पाकिस्तानी कार्यवाई के संकेतक के रूप में नहीं देखा। उत्तरी कमांड का अनुमान वह था कि पाकिस्तानी गतिविधियॉ हमेशा की तरह यह नियमित घुसपैठ और छिटपुट भिडंत है।
- इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा दी गई सूचनाओं को सैन्य कमांड तथा सैन्य इंटेलिजेंस द्वारा मई के प्रथम सप्ताह तक गंभीरता से नहीं लिया गया, विडंबना का एक विषय यह भी है कि रॉ और इंटेलिजेंस एजेंयिों की रिपोर्ट समय पर संयुक्त इंटेलिजेंस समिति के अध्यक्ष के पास क्यों नहीं भेजी गई।

कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना और मुजाहिद्दीनों द्वारा इतने बडे पैमाने पर घुसपैठ और वहीं बंकर बनाकर किलेबन्दी करना हमारे खुफिया तंत्र की बडी विफलता थी। इसकी जानकारी भी मार्ग में भेड बकरियॉ चराने वाले बकरवालों ने सेना को दी थी। इसकी जानकारी भारत के सत्रुओं पर पैनी नजर रखने वाली खुफिया एजेंसी रॉ को भी काफी बाद में हुई। कहा जाता है कि इस घुसपैठ की जानकारी पत्रकारों द्वारा सरकार को दी गई थी। हमारी खुफिया एजेंसियों की विफलता और सरकार की लापरवाही से हमें मई से लेकर 26 जुलाई तक इतिहास की सबसे बडी कठिन माउण्टेन पार लडनी पडी जिसमें हमे अपने 527 बहादुर सैनिक गॅवाने के साथ ही हमारे हजारों सैनिकों को घायल होना पडा।

हमारा राजनीतिक नेतृत्व और खासकर सेना के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराने वाला वित मंत्रालय पाकिस्तान के साथ ही चीन जैसे महाबली के विरूद्ध दो मोर्चों पर डंटी भारतीय सेना की ताकत बढाने के प्रति कितना सजग है उसका जीता जागता उदाहरण संसद की रक्षा मामलों की 40वी और 41वी रिपोर्ट ही काफी है। मेजर जनरल (सेनि) भुवन चन्द्र खण्डूडी की अध्यक्षता वाली रक्षा मामलों की संसदीय समिति की 40वी रिपोर्ट जब मार्च 2018 में संसद में पहुॅची तो समिति के अध्यक्ष जनरल खण्डूडी को 20 सितम्बर 2018 को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जबकि सामान्यतः कमेटी 5 वर्ष के लिए होती है इसलिए उसके अध्यक्ष को बीच में नहीं हटाया जाता है।

दरअसल खण्डूडी वाली समिति ने रक्षा तैयारियों में हो रही लापरवाहियों पर घोर चिन्ता प्रकट की थी। इस समिति ने रक्षा बलों पर हो रहे आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियों पर भी टिप्पणी की थी, लेकिन जब खण्डूडी की जगह वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद कलराज मिश्र को समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होने भी लगभग उन्ही बिन्दुओं पर अपनी चिन्तांए जाहिर की। इस मिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अगर किसी भी देश से पूर्ण और लम्बे समय तक चलने वाला युद्ध होता है तो भारतीय सेनाओं के पास 10 दिन का भी पूरा साजो सामान और गोला बारूद नहीं रहता।

निष्कर्षः–

कारगिल युद्ध में विजय का जश्न मनाते हुए हमे 20 वर्ष से ज्यादा हो गए। जश्न तो स्वाभविक ही है, क्योंकि यह दुनिया के युद्धों के इतिहास का एक असाधारण युद्ध था जो कि समुद्रतल से 17,500 फुट से अधिक ऊॅचाइयों पर बेहद कठिन चट्टानों पर भारत की सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और सवोच्च बलिदान की भावना से लडा गया और जीता भी गया। आण्विक शस्त्र बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। इस युद्ध में हमारे 527 जांबाज सैनिकों ने हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान का सर्वोच्च बलिदान दिया इनमें 75 जांबाज अकेले उत्तराखण्ड के थे। इस युद्ध में भारतीय सेयना ने दुनिया में एक बार फिर से अपना लोहा तो मनवाया मगर हमारे राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही ने कोई सीख नहीं ली। दरअसल कारगिल युद्ध सेकोई सबक लिया होता तो उसके बाद पुलवामा जैसे काण्ड नहीं होते और ना ही हमारे हजारों जांबाज सैनिकों अपनी जान से हाथ धोना पडता। युद्ध के कारण आर्थिक रू‍प से जो नुकसान उठाना पडा वह अलग है। इतने बडे कारगिल कांड से हमने अगर कुछ सीखा तोता तो पुलवामा में हमें अर्थ सैन्यबल के 40 जवानों को नहीं खोना पडता। पुलवामा से पहले पठानकोट, पम्पोर, उरी, बारामुला, हण्डवारा, शोपियां और जाकुरा में सैनिकों या सैन्य शिविरों पर भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के कई हमले हो चुके हैं और उस पर अभी पूर्णतया लगाम नहीं लगे हैं यह चिंता का विषय है।

संदर्भः

1. बर्नार्ड क्रिक, पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, (न्यूयॉर्कः बेसिक बुक्स, 1973)।
2. बारबरा गुडविन, राजनीतिक विचारों का उपयोग, (विले, 2000)।
3. कैटरीना मैकिनॉन, इश्यूज इन पॉलिटिकल थ्योरी, (नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), पृष्ठ 2।
4. माइकल ए. वेन्स्टीन, व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत, (कोलंबस, ओहियोः चार्ल्स ई. मेरिल 1971),
5. सीबी मैकफर्सन, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पी. 100, पारेख द्वारा उद्धृत, समकालीन राजनीतिक विचारक, लंदन, 1982।
6. वेंडी ब्राउन, एज वकर्रू क्रिटिकल एसेज ऑन नॉलेज एंड पॉलिटिक्स, (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005)।
7. भार्गव और आचार्य, राजनीतिक सिद्धांतः एक परिचय (नई दिल्लीः पियर्सन, 2008) में उद्धृत।
8. वैन ब्रैकेल, जे, 'प्राकृतिक प्रकार और जीवन के प्रकट रूप', डायलेक्टिका, संख्या 46 (1992) (पीपी. 243–259),